संख्या-197/2022/762/41-2022-113(बजट)/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 2022

विषयः- जनपद हरदोई के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बालामऊ वि0स0 में स्थित हत्याहरण स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की परियोजना हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8420/6-1-1(1227)/2020-21 दिनांक 26 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरदोई के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बालामऊ वि0स0 में स्थित हत्याहरण स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) द्वारा गठित किये गये आगणन के क्रम में आंकलित लागत रू 0 82.14 लाख जी0एस0टी0 सहित के सापेक्ष प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2021-22	संख्या -234 / 2021 / 413 / 41-2021-113 (बजट) / 2020 दिनांक 17.03.2021	82.14 लाख जी0एस0टी0 सहित	41.07 लाख

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 26.03.2022 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 41.07 लाख का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42-1, प्रगति रिपोर्ट, भौतिक प्रगति रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण आख्या, तकनीकी स्वीकृति, निविदा का आमंत्रण, ई-टेण्डर्ड नोटिस, स्वीकृति पत्र एवं परियोजना के अद्यतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 17.03.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है । प्रायोजना की अगली किश्त मांग करते समय 24 बिन्दुओं की पूर्ण सूचना, लेबरसेस, सेन्टेज चार्ज की सूचना, जी0एस0टी0 जमा कराये जाने का विवरण एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदो का वास्तविक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी -1192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020 231/2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित शर्तों एव प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा । निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य / मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा ।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय - समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय । स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार , प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा । वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय - ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर -2(9) (ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो - दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन : आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी । इसका अनुपालन महानिदेशक , पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा ।

(6) परियोजना में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या -07/2017/बी-1-823 /दस-2017-एम-04 /2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार , प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था / नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी ।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति / पुनरावृत्ति न हो और इसके रख - रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय - भार न पड़े । कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा । कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय । यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय । इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना / विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है । यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एव क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा । प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र / कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे ।

5. प्रस्तर-4 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -44 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्य-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

6. प्रस्तर-4 में अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या -3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

<u>संख्या व एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, हरदोई ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, (यूपीपीसीएल), लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, (यूपीपीसीएल), लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल ।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।